Millennium Post

16 January, 2018

No wellness schemes by firms, say 52% staff

NEW DELHI: More than half of corporate employees in India said their company does not run any wellness programme for them, a survey by Assocham said.

Adoption of corporate wellness programme can save India Inc income up to $20 billion by 2018 through a reduction in absenteeism rate by 1 per cent, the survey conducted across sectors such as Fast-moving consumer goods, media, IT/ ITeS and real estate, among others, said.

About 52 per cent of corporate employees revealed that their company does not run any wellness program for them, while 62 per cent of the remaining said the present wellness programme run by their organisation needs improvement, the survey report said.

Wellness programmes can improve chronic and lifestyle diseases of corporates and employees, according to the Assocham's latest paper 'Corporate Wellness Programme Benefits to Organisation and Economy'.

"On an average for every rupee being spent on employee wellness programme, employers get Rs 132.33 as a saving on absenteeism cost and Rs 6.62 back as reduced health care costs," the report said.

It further said while 83 per cent of sample population were willing to contribute part of

their salary in company sponsored wellness programme, 17 per cent do not intend to participate.

The paper noted that among IT/Information Technology Enabled Services employees, 93 per cent feel that company sponsored wellness programme act as motivating factor. In case of Fast-moving consumer goods, while 75 per cent of employees feel that it acts as a motivating factor, 25 per cent consider it as a depressing factor, the survey noted.

However, the chamber noticed that despite availability of preventive health care benefits through medical plans, most of the respondents do not take advantage for getting routine health care examination as some are not aware about benefits that exist and some hesitate to ask.

In its earlier survey, Assocham said a workplace wellness programme increases employees loyalty, improves work performance, boosts productivity and reduces attrition rate. PTI

Navbharat Times

16 January, 2018

थोक महंगाई दर घटकर 3.58% पर आई

[विशेष संवाददाता | नई दिल्ली]

दिसंबर माह में बेशक रिटेल महंगाई दर बढ़ी है, मगर इसी अवधि में थोक महंगाई दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। खाने-पीने की चीजों के दाम गिरने से थोक महंगाई दर दिसंबर 2017 में 3.58 फीसदी पर आ गई। नवंबर में यह आंकड़ा 3.93 फीसदी पर था, जो बाद में संशोधित होकर 3.68 फीसदी हो गया। गौरतलब है कि दिसंबर 2017 में रिटेल महंगाई 5.21 फीसदी पर पहुंच गई है। रिटेल महंगाई में तेजी फूड आर्टिकल्स खासकर सब्जियों की खुदरा कीमतों में तेजी के चलते आई है। एक्सपर्ट का कहना है कि थोक मूल्य महंगाई दर के आंकड़ों में आई नरमी से इस बात की उम्मीद तो जगी है कि आने वाले समय में रिटेल महंगाई में गिरावट आ सकती है। इंडस्ट्री चैंबर एसोचैम के प्रेसिडेंट संदीप जेजोदिया का कहना है कि थोक

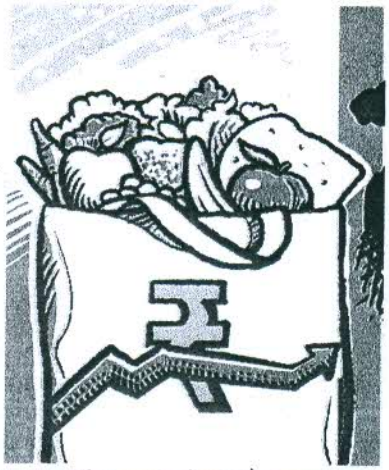

दर पर भी दबाव बनेगा और सरकार के पास महंगाई कम करने की गुंजाइश बढ़ेगी। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, खाने-पीने की चीजों की महंगाई दिसंबर में गिरकर 4.72 फीसदी पर आ गई, जो निवंबर में 6.06 फीसदी थी। सब्जियों की महंगाई दिसंबर में 56.46 फीसदी रही, जबकि नवंबर में यह 59.80 फीसदी पर दर्ज की गई थी। हालांकि, पिछले महीने प्याज की कीमतों में तेजी रही। प्याज की थोक महंगाई 197.05 फीसदी पर पहुंच गई, नवंबर में यह 178.19 पर थी। थोक महंगाई दर सूचकांक में फूड आर्टिकल्स की हिस्सेदारी 15.26 पर्सेंट और प्राइमरी आर्टिकल्स की हिस्सेदारी 22.62 फीसदी है।

फ्यूल एंड पावर सेगमेंट की थोक महंगाई दर दिसंबर में बढ़कर 9.16 फीसदी हो गई। नवंबर में यह 8.82 फीसदी पर थी। मैन्युफैक्चर्ड प्रॉडक्ट्स की महंगाई में कोई बदलाव नहीं हुआ।

Jansatta 16 January, 2018

थोक महंगाई दर में कमी, उद्योग जगत ने की नीतिगत दर में कटौती की मांग

नई दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा)।

थोक मुद्रास्फीति के दिसंबर में कम होकर 3.58 फीसद पर आने के साथ उद्योग जगत ने रिजर्व बैंक से निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये प्रमुख नीतिगत दर में कटौती की मांग दोहराई है।

उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष आर शाह ने कहा- मुद्रास्फीति का आंकड़ा बहुत हद तक आपूर्ति संबंधी कारकों से प्रभावित हैं, इसलिए हम रिजर्व बैंक से वृद्धि पर समान रूप से विचार करते हुए मौद्रिक नीति रुख में कुछ बदलाव पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा- आगामी मौद्रिक नीति में रेपो दर में कटौती निवेश को बढ़ावा देने तथा वृद्धि को गति देने के लिये महत्वपूर्ण है। एसोचैम ने कहा है कि मुद्रास्फीति 2018 में अप्रैल-जून तक ऊंची रह सकती है। हालांकि पिछले पांच महीने में विनिर्माण क्षेत्र की मुद्रास्फीति में वृद्धि चिंता का कारण हो सकता है। एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा- नीति निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में वृद्धि के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में निरंतर वृद्धि पर ध्यान देने की जरूरत है।

Vir Arjun

16 January, 2018

मुद्रास्फीति घटने से उद्योग जगत ने की नीतिगत दर में कटौती की मांग

नई दिल्ली, (भाषा)। थोक मुद्रास्फीति के दिसंबर में कम होकर 3.58 प्रतिशत पर आने के साथ उद्योग जगत ने रिजर्व बैंक से निवेश को बढ़ावा देने तथा आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये प्रमुख नीतिगत दर मे कटौती की मांग दोहराई है। उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष आर शाह ने कहा, मुद्रास्फीति का आंकड़ा बहुत हद तक आपूर्ति संबंधी कारकों से प्रभावित है, अत: हम रिजर्व बैंक से वृद्धि पर समान रूप से विचार करते हुए मौद्रिक नीति रुख में कुछ बदलाव पर विचार करने का अनुरोध करते है। उन्होंने कहा, आगामी मौद्रिक नीति में रेपो दर में कटौती निवेश को बढ़ावा देने तथा बृद्धि को गति देने के लिये महत्वपूर्ण है। एसोचैम ने कहा है कि मुद्रास्फीति 2018 में अप्रैल-जून तक ऊंची रह सकती है। हालांकि पिछले पांच महीने में विनिर्माण क्षेत्र की मुद्रास्फीति में वृद्धि चिंता का कारण हो सकता है। एसोचैम के महासचिव डी एस रावत ने कहा, नीति निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में वृद्धि के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में निरंतर वृद्धि पर ध्यान देने की जरूरत है। इसका आयात बिल पर प्रभाव पड़ सकता है जिससे मुद्रा की विनिमय दर भी प्रभावित हो सकती है। यहां आज जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार खाद्य समूह की महंगाई दर दिसंबर में 4.72 प्रतिशत रही जो नवंबर 2017 में 6.06 प्रतिशत थी। शाह ने कहा, हम खाद्य वस्तुओं के प्रभावी प्रबंधन के लिये कृषि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में बजट में अधिक स्पष्ट उपायों को लेकर आशान्वित है। हम आने वाले महीनों में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की उम्मीद करते है जिससे ईंधन मुद्रास्फीति में कमी लाने में मदद मिलेगी।

Virat Vaibhav

16 January, 2018

राहत *थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2017 में कम होकर 3.58 प्रतिशत रही*

खाद्य वस्तुओं के दाम घटने से थोक मुद्रास्फीति में नरमी

एजेंसी ■ नई दिल्ली

खाद्य वस्तुओं के दाम घटने से थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2017 में कम होकर 3.58 प्रतिशत रही। हालांकि, इस दौरान ईंधन की कीमत में वृद्धि दर्ज की गई। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति एक महीना पहले नवंबर 2017 में 3.93 प्रतिशत तथा एक साल पहले दिसंबर में 2.10 प्रतिशत थी। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार खाद्य समूह की महंगाई दर दिसंबर में 4.72 प्रतिशत रही जो नवंबर 2017 में 6.06 प्रतिशत थी। सब्जियों की मुद्रास्फीति में कुछ नरमी रही। दिसंबर में इस खंड में सालाना आधार पर महंगाई दर 56.46 प्रतिशत रही जो इससे पिछले महीने 59.80 प्रतिशत थी। हालांकि, प्याज का थोक भाव दिसंबर में 197.05 प्रतिशत बढ़ गया। आंकड़े के अनुसार अंडा, मांस और मछली जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की महंगाई दर दिसंबर में घटकर 1.67 प्रतिशत रही। हालांकि, फल के मामले में यह बढ़कर 11.99 प्रतिशत रही। ईंधन एवं बिजली खंड में थोक मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 9.16 प्रतिशत रही जबकि विनिर्माण वस्तुओं के मामले में यह 2.61 प्रतिशत थी। पिछले सप्ताह जारी आंकड़े के अनुसार खाद्य वस्तुओं खासकर सब्जियों के दाम बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 5.21 प्रतिशत पहुंच गई जो रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर है। रिजर्व बैंक मुख्य नीतिगत दर पर निर्णय करते समय खुदरा मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है। रिजर्व बैंक ने दिसंबर में मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर को यथावत रखा। वहीं चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर 4.3 से 4.7 प्रतिशत कर दिया। इसका कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में तेजी और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लागू होना है।

उद्योग जगत ने की नीतिगत दर में कटौती की मांग

नई दिल्ली। थोक मुद्रास्फीति के दिसंबर में कम होकर 3.58 प्रतिशत पर आने के साथ उद्योग जगत ने रिजर्व बैंक से निवेश को बढ़ावा देने तथा आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए प्रमुख नीतिगत दर में कटौती की मांग दोहराई है। उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष आर शाह ने कहा, मुद्रास्फीति का आंकड़ा बहुत हद तक आपूर्ति संबंधी कारकों से प्रभावित है, अतः हम रिजर्व बैंक से वृद्धि पर समान रूप से विचार करते हुए मौद्रिक नीति रुख में कुछ बदलाव पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा, आगामी मौद्रिक नीति में रेपो दर में कटौती निवेश को बढ़ावा देने तथा वृद्धि को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। एसोचैम ने कहा है कि मुद्रास्फीति 2018 में अप्रैल-जून तक ऊंची रह सकती है। हालांकि पिछले पांच महीने में विनिर्माण क्षेत्र की मुद्रास्फीति में वृद्धि चिंता का कारण हो सकता है। एसोचैम के महासचिव डी एस रावत ने कहा, नीति निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में वृद्धि के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में निरंतर वृद्धि पर ध्यान देने की जरूरत है।

Naiduniya

16 January, 2018

घरेलू उद्योग जगत ने की ब्याज दरें घटाने की मांग

नई दिल्ली। दिसंबर में थोक मंहगाई थोड़ी कम होने के बाद उद्योग जगत ने रिजर्व बैंक से नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का आग्रह किया है, ताकि निवेश बढ़े और देश की आर्थिक तरक्की को बढ़ावा मिल सके। उद्योगों का मानना है कि चूंकि महंगाई के आंकड़े एक हद तक आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करते हैं, लिहाजा आरबीआई को मौद्रिक नीति इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए कि उसमें विकास से जुड़े मसलों को भी बराबर जगह मिल सके। उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष रशेश शाह ने कहा, 'आगामी मौद्रिक नीति में रेपो रेट में कटौती निवेश को रफ्तार देने और विकास दर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।' उधर एसोचैम का कहना है कि पिछले 5 महीनों के दौरान कोर इंफ्लेशन के रुख को प्रमुख कारक मानते हुए कहा जा सकता है कि महंगाई अप्रैल से जून 2018 तक तेज रह सकती है। एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा, 'नीतिनिर्माताओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है।'